नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

कर्तव्यों को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : मोदी

नई दिल्ली, 26 नवंबर . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर नागरिकों से आह्वान किया कि वे 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित पत्र में 1949 में संविधान को अपनाए जाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का स्मरण किया तथा इसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शक बताया.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कर संविधान के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत किया. मोदी ने उल्लेख किया कि भारत का संविधान साधारण पृष्ठभूमि के नागरिकों को भी सर्वोच्च पदों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है. उन्होंने 2014 में संसद की सीढ़ियों पर नमन करने और 2019 में संविधान को माथे पर धारण करने की अपनी स्मृतियों का भी उल्लेख किया.

प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के महान सदस्यों, विशेष रूप से डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. बी. आर. अंबेडकर के योगदान को नमन करते हुए कहा कि संविधान ने करोड़ों नागरिकों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति दी है. उन्होंने कहा कि यह वर्ष संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह सरदार पटेल, भगवान बिरसा मुंडा, वंदे मातरम के 150 वर्ष और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के साथ संयोग बना रहा है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 51(ए) में निहित मौलिक कर्तव्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति की नींव हैं. उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए वर्तमान नीतियों के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि देश की दिशा उन फैसलों से तय होगी, जो आज लिए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने युवाओं से मतदान के अधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की भी अपील की.

'संविधान राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ' : मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर कहा कि संविधान भारत की राष्ट्रीय पहचान और अस्मिता का मूल ग्रंथ है. केन्द्रीय कक्ष में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद ने बीते दशक में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों को साकार किया है. उन्होंने समावेशी विकास, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और आपराधिक न्याय सुधारों को संविधान की भावना के अनुरूप बताया तथा संविधान निर्माताओं को राष्ट्र की ओर से नमन किया. इस अवसर पर उप राष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन,प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सभी सांसद मौजूद थे.

संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच : राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संविधान दिवस पर कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक से किया गया पवित्र वादा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि समानता, सम्मान और न्याय का अधिकार संविधान की देन है, और इसे कमजोर करने का हर प्रयास रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सुरक्षित है, तब तक हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं. उन्होंने नागरिकों से इसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की.

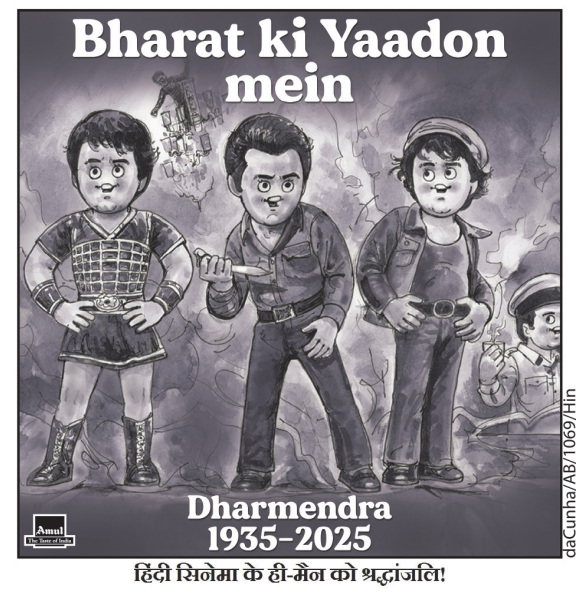

हिंदी सिनेमा के ही-मैन को श्रद्धांजलि!

रेयर अर्थ मैगनेट निर्माण के लिए 7,280 करोड़ की योजना को मंजूरी

नई दिल्ली, 26 नवंबर . केंद्र सरकार ने भू-रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेयर अर्थ मैगनेट के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 7,280 करोड़ रुपये की सात वर्षीय प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत अगले चार से पाँच वर्षों में देश में कम से कम 6,000 टन सिंटर्ड रेयर अर्थ मैगनेट के उत्पादन क्षमता वाली पाँच विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिनकी वार्षिक क्षमता 1,200-1,200 टन होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सूचना प्रसारण, रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैगनेट विनिर्माण संवर्धन योजना भारत की सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष और रक्षा विनिर्माण क्षमता को मजबूत करेगी. वर्तमान में भारत जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया से रेयर अर्थ मैगनेट का आयात करता है, जबकि चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसने हाल ही में निर्यात प्रतिबंध लगाए थे.

योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दोनों दिए जाएंगे. 7,280 करोड़ रुपये में से 6,450 करोड़ रुपये बिक्री आधारित प्रोत्साहन तथा 750 करोड़ रुपये पूंजीगत सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे. योजना की कुल अवधि सात वर्ष होगी, जिसमें शुरुआती दो वर्ष परियोजना स्थापना के लिए निर्धारित हैं. भारत में वर्तमान में रेयर अर्थ मैगनेट की सालाना मांग 4,000-5,000 टन है.

आतंकवादी उमर को पनाह देने वाले को किया गिरफ्तार

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राजधानी में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट की वारदात को अंजाम देने वाले आतंकवादी उमर उन नबी को पनाह देने के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. फरीदाबाद के धौज का रहने वाला शोएब इस मामले में गिरफ्तार होने वाला सातवां आरोपी है. एनआईए की जांच से पता चला है कि शोएब ने 10 नवंबर को कार बम धमाका होने से पहले उमर को रसद सहायता प्रदान की थी. इस धमाके में कई लोग मारे गये थे तथा कई अन्य घायल हुए थे.

कर्नाटक का विवाद जल्द सुलझेगा

राहुल गांधी का डीके एस को टेक्स्ट मैसेज

कर्नाटक,26 नवम्बर . कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक सप्ताह बाद जवाब भेजते हुए लिखा— 'कृपया इंतज़ार करें, मैं आपको कॉल करता हूं.' शिवकुमार पिछले हफ्ते से ही राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांग रहे थे.

सूत्रों के अनुसार, पार्टी आलाकमान चाहता है कि कर्नाटक का विवाद 1 दिसंबर तक सुलझा लिया जाए. इस बीच,

राहुल गांधी ने दिल्ली में कर्नाटक के दो नेताओं— प्रियांक खरगे और शरत बच्चेगौड़ा के साथ एक अहम बैठक की. इसमें 'वोट चोरी' के आरोप, वोटर-रिविजन एक्टिविटी, एमजीओ चिलुमे की कथित भूमिका, साथ ही नया लॉन्च हुआ.

सवर्ण समाज एफआईआर व बर्खास्तगी पर अड़ा

▸ पैदल मार्च कर एसपी ऑफिस का घेराव

नवभारत न्यूज

भोपाल,26 नवम्बर . प्रदेश भर में भोपाल सहित कई जिलों में ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों में आईएएस संतोष वर्मा के कथित विवादित बयान को लेकर भारी आक्रोश फैल गया है. जगह-जगह धरना, प्रदर्शन, रैलियां और ज्ञापन का दौर जारी है.

ग्वालियर से दतिया तक समाज के प्रतिनिधि वर्मा के खिलाफ एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग पर अडिग हैं.

विरोध इतना व्यापक हो चुका है कि विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है.

41 माओवादी कैडरों ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर, 26 नवंबर . छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बुधवार को माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ, जब 41 सक्रिय माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. इन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपये का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वालों में 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं.

आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में पीएलजीए बटालियन-1 के सदस्य, एरिया कमेटी मेंबर, प्लाटून कमांडर, मिलिशिया कमांडर तथा जनताना सरकार के पदाधिकारी शामिल हैं. इनके अलावा कई कैडर दक्षिण सब-जोनल ब्यूरो, तेलंगाना स्टेट कमेटी और धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ डिवीजन से जुड़े थे. सबसे अधिक इनामी कैडर पण्डरू हपका उर्फ मोहन और बण्डी हपका थे, जिन पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था.

> पुलिस ने इसे राज्य सरकार की 'पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन' नीति और 'नियद नेल्ला नार' योजना की बड़ी सफलता बताया. सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और परिवारों की अपील ने इन माओवादियों को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया. सरेंडर करने वालों को तुरंत 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी तथा आगे पुनर्वास प्रक्रिया शुरू होगी.

मुठभेड़ में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के चार गुर्गे गिरफ्तार

मोहाली, 26 नवम्बर. पंजाब में एक बड़ी आतंकवादी साज़िश नाकाम करते हुए एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और एसएएस नगर पुलिस ने बुधवार अपराह्न डेरा बस्सी-अंबाला हाईवे पर स्टील स्ट्रिप्स टावर्स के पास गोलीबारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विदेश में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के चार गुर्गों को पकड़ लिया. पुलिस महानिदेशक यादव ने बताया कि हाईवे के किनारे एक घर में छिपे आरोपियों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान पुलिस पर गोलियां चलाईं.

दुष्कर्म का आरोपी अब भी फरार

रायसेन,26 नवम्बर . गौहरगंज में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने से लोगों का आक्रोश मंगलवार को उग्र हो गया. सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक रूप ले बैठा, जब कार्यक्रम के बाद लौटते समय कुछ युवक मुस्लिम बावली बस्ती की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी.

स्थिति बिगड़ते ही पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. इसके बाद उपद्रवी मौके से भाग निकले. घटनास्थल पर तनाव को देखते हुए गौहरगंज में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं. रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा सहित छह जिलों से 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

डीआईजी प्रशांत खरे ने बताया कि हालात अब नियंत्रण में हैं और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी सलमान अभी तक फरार है, जिसकी तलाश में कई टीमें दबिश दे रही हैं.

राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर याचिका पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली, 26 नवंबर . राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर केस ट्रांसफर याचिका पर बुधवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया है. याचिका में मांग की गई है कि मामले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने को बदला जाए और केस किसी अन्य जज को सौंपा जाए.

राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि जज का रवैया पक्षपातपूर्ण है और न्यायिक दृष्टिकोण उनके प्रति निष्पक्ष नहीं दिख रहा. इसी आधार पर उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस ट्रांसफर की मांग की है. जज विशाल गोगने इस मामले में आरोप तय करने और आगे की सुनवाई कर रहे हैं.

बड़ा ऐलान | किसानों को भावांतर की बड़ी सौगात, विकास कार्यों को दी झड़ी

खातों में 249 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

नव भारत न्यूज

इंदौर, 26 नवम्बर . गौतमपुरा में बुधवार को आयोजित बड़े किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए 1.34 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 249 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. उन्होंने कहा कि किसान और जवान दोनों देशसेवा में समान भाव से समर्पित हैं और राज्य सरकार हर कीमत पर अन्नदाता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

गौतमपुरा का विशाल मैदान किसानों की भारी उपस्थिति से उत्साहित नजर आया. सीएम ने बताया कि अब तक 4.39 लाख किसानों द्वारा 7.85 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन बेचा जा चुका है और सरकार बाजार भाव में आई भारी गिरावट की पूरी भरपाई किसानों को लौटा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान को उसकी उपज का न्यायपूर्ण दाम मिले और उसके परिवार की समृद्धि सुनिश्चित हो. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंदौर जिले को 264 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का पैकेज भी दिया. उन्होंने इनगोरिया-देपालपुर (शेष पेज 12 पर)

> **हर खेत तक सिंचाई और सोलर पावर की सुविधा**
> मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को धन और पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने बताया कि देपालपुर क्षेत्र में 1538 करोड़ रुपये की लागत से चंबल नदी पर बैराज बन रहा है, जिससे 27 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि और 75 गांव लाभान्वित होंगे. सोलर पावर पंप योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसान अब घर, खेत और दुकान तक अपनी ही बिजली से रोशनी कर सकेंगे, जिससे ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढ़ेगी.